विधानसभा चुनाव में सीमा की राह में होंगे असीमित रोड़े

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) । बड़खल विधानसभा से दो बार की विधायक सीमा त्रिखा की अगले विधानसभा चुनाव का टिकट पाने की राह आसान नहीं होगी। बीते विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर बहुत घट जाने के कारण सीमा के टिकट पाने की संभावनाएं काफी सीमित हो गई हैं। वहीं इस विधानसभा से तीन कद्दावर पंजाबी भाजपाई भी सीमा का टिकट झटकने के दावेदार हैं। धनपशु करतार भड़ाना भी बेटे के लिए भाजपा का टिकट खरीदने का दम भर रहे हैं।

2014 में कांग्रेस विरोधी और मोदी लहर पैदा किए जाने के कारण केंद्र के साथ ही हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनी थी। बड़खल विधायक सीमा त्रिखा ने कांग्रेस विधायक महेंद्र प्रताप सिंह को 36,609 वोटों के अंतर से मात दी थी। सीमा को 70,218 वोट मिले थे जबकि महेंद्र प्रताप महज 33,

सीमा त्रिखा

धनेश अदलखा

राजीव जेटली

राजन मुथरेजा

609 वोट ही पाए थे। सीमा की इस जीत में मोदी लहर के साथ पहली बार सांसद बने किशन पाल गूजर का हाथ रहा। अधिकतर गूजर मतदाताओं ने महेंद्र प्रताप का साथ छोड़ सत्ता के नए केंद्र बने किशनपाल गूजर के इशारे पर सीमा को वोट दिए थे।

सत्ता मिलते ही बेकाबू हुईं सीमा त्रिखा ने खुद को पंजाबी समुदाय का नेता साबित करने के लिए ने पहले से स्थापित पंजाबी नेताओं के पर कतरने शुरू कर दिए। एनआईटी तीन दशहरा मैदान में रावण दहन, एनआईटी एक नंबर हनुमान मंदिर प्रबंधन में सीमा त्रिखा ने विधायक चंदर भाटिया के भाई राजेश भाटिया, जगदीश भाटिया के विरोधियों को समर्थन दिया। इस उठापटक में सीमा त्रिखा को कुछ नए समर्थक मिले तो काफी विरोधी भी तैयार हो गए। विरोधियों को कमजोर करने की जुगत में लगीं सीमा पहले कार्यकाल में कोई उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं करा सकीं। नतीजा हुआ कि आम जनता उनसे नाराज हो गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो बमुश्किल ढाई हजार के अंतर से चुनाव जीत सकीं। राजनीतिक जानकार इसे प्रशासन की मेहरबानी बताते हैं। बताया जाता है कि मतगतणना के अंतिम चरण तक कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप करीब सात हजार मतों के बड़े अंतर से आगे चल रहे थे। अंतिम बैलट मशीन की मतगणना के समय मीडिया को बाहर कर दिया गया और कुछ समय बाद सीमा त्रिखा को ढाई हजार वोटों के अंतर से जीता घोषित कर दिया गया था। इस चुनाव में उनका यानी भाजपा का वोट बैंक करीब 17 प्रतिशत घटा था जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के मत पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़े थे। सीमा चुनाव कैसे जीतीं इस पर नहीं जाएं तो भी जनता में उनकी घटती लोकप्रियता तो सामने आ ही गई। बताया यह भी जाता है कि इस चुनाव में सीमा त्रिखा को पंजाबी समाज ने दरकिनार कर दिया था, उनको यह छोटी सी जीत गूजर मतदाताओं के कारण मिली थी।

उनकी जीत की हक़ीक़त भाजपा आलाकमान को तो मालूम ही है। दूसरे कार्यकाल में भी खट्टर सरकार की तरह सीमा की साख भी लगातार गिरती नजर आ रही है। भरोसेमंद सूत्रों का मानना है कि सीमा यदि इस बार चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। ऐसे में आला कमान दूसरे चेहरों पर दांव खेल सकता है। इनमें दो नाम प्रमुख हैं पहला भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली और दूसरा धनेश अदलखा। इनके अलावा बडखल विधानसभा कोषाध्यक्ष राजन मुथरेजा भी बड़े दावेदार हैं। ये तीनों ही पंजाबी समुदाय से आते हैं।

यहां बताना जरूरी है कि बड़खल विधानसभा पंजाबी मतदाता बाहुल सीट है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यहां करीब एक लाख पंजाबी, पचास हजार दलित, पच्चीस हजार गूजर वोटर हैं। इनके अलावा सवर्ण, मुस्लिम और ओबीसी वोट करीब पंद्रह हजार हैं। जातिगत राजनीति से दूर रहने वाली भाजपा यहां से पंजाबी प्रत्याशी को तरजीह देती है। इस आधार पर राजीव जेटली, धनेश अदलखा और राजन मुथरेजा की दावेदारी मजबूत दिख रही है।

खट्टर के करीबी राजीव जेटली राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बावजूद अधिकतर समय इसी विधानसभा क्षेत्र में ही बिताते हैं, पार्टी आलाकमान में भी उनकी बेहततरीन पकड़ बताई जाती है। नगर निगम चलाने वाला बेताज बादशाह कहे जाने वाले धनेश अदलखा भी सीएम खट्टर के खास बताए जाते हैं। बड़खल में होने वाले खट्टर के किसी भी कार्यक्रम में वह प्रमुखता से नजर आते हैं। कोषाध्यक्ष राजन मुथरेजा भी प्रमुख दावेदार हैं। इन तीनों नेताओं की जनता में पकड़ हो न हो, आला कमान में अच्छी पकड़ हैं और तीनों ही सीमा की गिरती साख को अपने हक में भुनाने के लिए भाजपा आला कमान से लेकर सीएम कार्यालय तक सक्रिय हैं।

भाजपा के इन पदाधिकारियों के अलावा धनपशु करतार भड़ाना अपने बेटे मनमोहन भड़ाना को बड़खल विधानसभा से टिकट दिलाने की कवायद में जुटे हैं। कांग्रेस, भाजपा सहित सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों से मधुर संबंध रखने वाले करतार के बारें में कहा जाता है कि वह पैसे के दम पर किसी भी पार्टी का टिकट खरीदने की क्षमता रखते हैं। भाजपा के जानकारों का भी मानना है कि आला कमान तक पहुंच रखने वाले करतार बेटे मनमोहन को टिकट दिलवा सकते हैं।

सीमा की दावेदारी घटने का एक और कारण उनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक होना भी है। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले, पिछले चुनाव में बहुत कम मतांतर से जीतने वाले विधायकों की जगह नए और युवा चेहरों को टिकट दिया है। संघ व भाजपा आला कमान हरियाणा में एंटी इन्कंबेंसी यानी सरकार विरोधी लहर के प्रति चिंतित है। ऐसे में सरकार की साख बचाए रखने के लिए तीन राज्यों वाला दांव यहां भी लागू किया जा सकता है। सीमा त्रिखा इन दोनों कसौटियों यानी 35 से 55 की उम्र और अधिक वोटों के अंतर से जीत, पर फेल नजर आती हैं। इसके विपरीत, धनेश अदलखा, राजीव जेटली, राजन मुथरेजा और मनमोहन भड़ाना चुवा और नए चेहरे हैं। इन परिस्थितयों के साथ सीमित होते जनाधार और घटती लोकप्रियता के बीच सीमा को अपना टिकट बरकरार रखने के लिए असीमित मेहनत करनी पड़ सकती है।

खट्टर के भी चुनाव लड़ने की चर्चा

राजनीतिक हलकों में खट्टर के भी बड़खल विधानसभा चुनाव से प्रत्याशी होने की चर्चाएं हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सीएम सिटी होने के बावजूद करनाल का कोई विकास नहीं हो सका है। शहर में आधारभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रही जनता की नाराजगी आए दिन होने वाले धरने-प्रदर्शन आदि में देखी जा सकती है। ऐसे में खट्टर के लिए दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ने का विकल्प भी तैयार किया जा रहा है। पंजाबी मतदाता बाहुल होने के कारण खट्टर को बड़खल विधानसभा से भी उतारा जा सकता है। इसके लिए संघ-भाजपा ही नहीं खट्टर खुद भी कई साल से जमीन तैयार कर रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए खट्टर ने निजी बिल्डरों की बसाई ग्रीन फील्ड कॉलोनी, सैनिक कॉलोनी की करोड़ों रुपये की ईडीसी आईडीसी दर किनार करते हुए यानी सरकारी खजाने को चुना लगाते हुए इन्हें रेगुलराइज करने की रेवड़ी बांटी। यही नहीं एनआईटी एक, दो, तीन और पांच में लीज पर दी गई सरकारी प्रॉपटी की रजिस्ट्री करा कर पंजाबी समुदाय को लुभाया गया। माना जा रहा है कि यदि खट्टर बड़खल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो पंजाबी समुदाय उन्हें इन रेवड़ियों के बदले वोट देकर उनका अहसान चुकाएगा।

रेडक्रॉस सोसायटी : भ्रष्टाचार छिपाने के लिए उड़ा रहे आरटीआई कानून की धज्जियां

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। भ्रष्टाचार में डूबी जिला रेडक्रॉस सोसायटी के अधिकारी काले कारनामे छिपाने के लिए आरटीआई एक्ट की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आरटीआई लगाने वाले बीपीएल परिवार के छात्र को निशुल्क जानकारी देने के बजाय जिला सचिव बिजेंद्र सौरोत ने उल्टे उससे सूचना मांग डाली कि आरटीआई एक्ट में बीपीएल परिवार को निशुल्क जानकारी देने का प्रावधान कहां है ? सूचना देने के लिए उससे दस्तावेजों की प्रति की इतनी रकम मांग ली गई कि वह चुका न सके और भ्रष्टाचार दबा ही रह जाए।

रेडक्रॉस के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार वर्ष 2020 से 2022 के बीच किसी वर्ष दिवाली पर गिफ्ट खरीदने के नाम पर सोसायटी के पदाधिकारियों के बीच ढाई लाख रुपये का बंदरबांट हुआ है। बताते चलें कि यह हेराफेरी भी कोरोना काल के दौरान हुई, जब यहां ऑक्सीजन-सिलिंडर घोटाले के सूत्रधार विमल खंडेलवाल, सचिव विकास और क्लर्क जतिन शर्मा का बोलबाला था। जतिन शर्मा वही है जिसने रेडक्रॉस सोसायटी में ट्रेनिंग के दो बैचों के अभ्यर्थियों से वसूले गए साठ हजार रुपये हड़प लिए थे। अंदरखाने खुलासा होने के बावजूद रेडक्रॉस के भ्रष्ट आला अधिकारी उसे बचाने में जुटे हैं। सोसायटी अध्यक्ष व जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने भी इतने दिन बीतने के बावजूद आज तक ढाई लाख रुपयों का हिसाब किताब नहीं मांगा है। उनकी चुप्पी भ्रष्टाचार में उनकी मिलीभगत होने की आशंका पर बल दे रही है।

भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि कोरोना काल के दौरान दिवाली गिफ्ट खरीदने के नाम पर सोसायटी के खजाने से ढाई लाख रुपये नकद निकाले गए थे। न तो गिफ्ट खरीदे गए और न ही ढाई लाख रुपयों का कोई हिसाब दिया गया। जाहिर है इतनी बड़ी रकम अकेला कोई एक व्यक्ति हजम नहीं कर सकता। उस समय सक्रिय भ्रष्ट, लूटखोर, दागी पदाधिकारियों के बीच यह धनराशि बंटी होगी। यह रकम सोसायटी के अकाउंट में बट्टे खाते में पड़ी है। घोटाले करने वाले जतिन शर्मा और विकास को गुड़गांव ट्रांसफर कर दिया गया। उनके बाद आने वाले सचिव व अन्य पदाधिकारियों को इस लूट खसोट की जानकारी तो हुई लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय इस पर पर्दा डाले रखा। डीसी विक्रम यादव इस घोटाले के बाद से कई बार रेडक्रॉस सोसायटी के क्रियाकलापों की समीक्षा का चुके हैं, संभव नहीं है कि यह घोटाला उनकी जानकारी में न हो। ऐसे में आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाना उनकी ईमानदारी और योग्यता पर भी प्रश्नचिह्न है।

रेडक्रॉस सोसायटी के ढाई लाख रुपये हड़पने वाले पदाधिकारियों को सामने लाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवार के कक्षा नौ के छात्र एनआईटी पांच निवासी दिपांशु पाठक ने 25 सितंबर 2023 को रेडक्रॉस सोसायटी में आरटीआई लगाई। इसमें उन्होंने सोसायटी के सचिव और राज्य जन सूचना अधिकारी बिजेंद्र सौरोत से वर्ष 2020-21, 22 तक की जिला रेडक्रॉस सोसायटी व सेंट जॉन एंबुलेंस की बैलेंस शीट और लेजर की प्रमाणित छाया प्रति मांगी। इस दौरान की कैशबुक और कैश वाउचर की भी छाया प्रति मांगीं। इस दौरान हुए इंटरनल ऑडिट की प्रमाणित छाया प्रति की भी मांग की गई।

दिपांशु ने सूचना मुफ्त पाने के लिए अपने बीपीएल राशन कार्ड की छायाप्रति और स्कूल का पहचान पत्र भी लगाया। बताते चलें कि आरटीआई एक्ट की धारा 7 की उपधारा 5 में फीस एवं सूचना की लागत से छूट का प्रावधान है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति से नमूने की लागत के अतिरिक्त को शुल्क नहीं लिया जा सकता। एक्ट के आधार पर राज्य जन सूचना आयोग ने अनेकों बार निर्णय दिया है कि यदि आवेदक को एक माह के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो उसे सारी जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

एसपीआइओ बिजेंद्र सौरोत ने एक माह के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई। उन्हें 20 नवंबर को दिपांशु ने ईमेल रिमाइंडर भेजा। इस पर राज्य जन सूचना अधिकारी का जिम्मा निभा रहे सचिव बिजेंद्र सौरोत ने आरटीआई एक्ट के प्रति अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुई उल्टे दिपांशु से ही जवाब मांग लिए। उनका जवाब था कि एसपीआईओ व सचिव जिला रेडक्रॉस सोसायटी की जानकारी के अनुसार बीपीएल कार्ड धारक को सौ पेज तक निशुल्क जानकारी दी जा सकती है। इस कार्यालय में ऐसे किसी नियम की कॉपी उपलब्ध नहीं है, ऐसी कोई धारा या नियमावली की आपको जानकारी हो तो कार्यालय को देने का कष्ट करें।

समझा जा सकता है कि जिस जनसूचना अधिकारी को आरटीआई एक्ट (जो कि कार्यालय रिकॉर्ड के अलावा ऑनलाइन भी उपलब्ध है) की धाराओं, उपधाराओं और नियमों की जानकारी नहीं है वो कितनी सटीक सूचना उपलब्ध कराएगा। सूचना फिर भी नहीं दी गई और समय पर सूचना नहीं दिए जाने का कारण बताया गया कि कार्यालय में ऑडिट का काम चल रहा है जिस कारण खाता बही, रोकड़ बही, बैलेंस शीट आदि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास रखे हुए थे।

वहां से दस्तावेज मिलने पर बताया गया कि पेजों की संख्या काफी अधिक है जिनकी गिनती करने में समय लगा। हैरानी की बात यह है कि सारा लेखा जोखा ऑडिटर के पास अभी तक पड़ा हुआ था जबकि यह 2020 से संबंधित है ऐसा जान पड़ता है कि आरटीआई लगने के बाद ही विभाग ने ऑडिटर कार्यालय से ये दस्तावेज मंगाए, यानी ऑडिट के नाम पर भी बस खानापूर्ति का खेल खेला जाता है। सूत्रों के अनुसार दिपांशु को बताया गया है कि सभी दस्तावेजों की छाया प्रति करीब तेईस सौ हैं इसके लिए दो रुपये प्रति छायाप्रति का भुगतान किए जाने पर सूचना दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि ढाई लाख रुपयों के गबन की शक की सुई क्लर्क जतिन शर्मा की और पुख्तगी से इशारा कर रही है लेकिन जिला सचिव सोसायटी के आला पदाधिकारियों के इशारे पर सूचना देने में आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि ये आला अधिकारी अपने चहेते भ्रष्टाचारी कर्मचारी को बचा रहे हैं।

आरटीआई एक्टिविस्ट एंड सिटिजन वॉयस एसोसिएशन के महासचिव रवींद्र चावला कहते हैं कि सरकारी कार्यालयों के दस्तावेज भी सूचना के अधिकार के तहत ही आते हैं। आरटीआई एक्ट में ही प्रावधान है कि यदि दस्तावेज बहुत ज्यादा हैं तो पचास रुपये शुल्क लेकर सीडी या फ्लॉपी में सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाए। अधिकारी जानबूझ कर इन प्रावधानों की अनदेखी कर आवेदक को जबरन परेशान करते हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।